लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हों
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

चार रुपये

Price : *Four Rupees*

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 13, शनिवार, 25 जून, 1977/4 आषाढ़, 1899 (शक)
No. 13, Saturday, June 25, 1977/Asadha 4, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	1
योग उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक	Yoga Undertakings (Taking over of Management) Bill . . .	1
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain	1
(खण्ड 2 से 16 तथा 1)	(Clauses 2 to 16 and 1)	2
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass .	2
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain	2
अनुदानों की मांगें, 1977-78	Demands for Grants, 1977-78 .	3
वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय	Ministry of Commerce and Ministry of Civil Supplies and Cooperation .	
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai	3
प्रो० आर० के० अमीन	Prof. R. K. Amin . . .	5
चौधरी ब्रह्म प्रकाश	Chaudhury Brahm Parkash .	7
श्रीमती अहिल्या पी० रंगनेकर	Shrimati Ahilya P. Rangnaekar	8
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . . .	9
श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला	Shri Parmanand Govindjiwala .	10
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	10
श्री अनन्त देव	Shri Anant Dave . .	12
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde .	12
श्री युवराज	Shri Yuvraj . .	14
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	15
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe .	16
श्री ए० मुरुगेसन	Shri A. Murugesan . .	16
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma .	17
श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा	Shri Mritunjay Prasad Verma . .	18
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . . .	19
श्री धर्मसिंहभाई पटेल	Shri Dharmasinhbhai Patel	20
श्री तेज प्रताप सिंह	Shri Tej Pratap Singh	20
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu . . .	20
श्री मोतीभाई आर० चौधरी	Shri Motibhai R. Chaudhary .	21
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan . .	22

लोक सभा
LOK SABHA

शनिवार, 25 जून, 1977/4 आषाढ़, 1899 (शक)
Saturday, June 25, 1977/Asadha 4, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए / *Mr. Speaker in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत रखी गई अधिसूचनाएं

वित्त और राजस्व और बैंककारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अधिसूचना संख्या 95—सीमा-शुल्क जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल०टी० 540/77)

(दो) अधिसूचना संख्या 96–सीमा-शुल्क और 97–सीमा-शुल्क जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(ग्रंथालय में रखा गया / देखिये सं० एल० टी० 541/77)

योग उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक—जारी
YOGA UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL—contd.

Sh. Raj Narain: Sir, Yesterday an hon'ble Member had made an allegation that false entries have been made in the visitor's register with a view to malign Sh. Dhirendra Brahmchari. This allegation is baseless and to prove my statement. I have brought the register with me which bears the signatures of the Magistrate, Commissioner as well as of Dhirendra Brahmchari on every page. We have no intention of maligning any body.

I am not stating anything which is unparliamentary. If some hon'ble Member asks any question it is my duty to reply to that.

श्री दीनेन भट्टाचार्य :—Please tell us if he is a 'Brahmachari'?

Sh. Raj Narain :*

अध्यक्ष महोदय : जिन शब्दों पर आपत्ति है उन्हें सभा की कार्यवाही से निकालने के प्रश्न पर मैं विचार करूंगा। अध्यक्ष के पास यही अधिकार है। हमें सभा की कार्यवाही भी चलानी है।

Sh. Raj Narain : I never violate the parliamentary procedure. Sir, if you permit me I can lay the register on the Table of the House. Members are welcome to have a look into it.

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।
*Expunged as ordered by the Chair.

Moreover I am not bringing any politics in this matter. You can yourself judge whether it was a Yogashram or a Bhogashram. Sh. Yashpal Kapoor's name has also been mentioned and it has been said that he had been appointed a member of the Governing body of the Central Yoga Research Institute by this Parliament. An enquiry was made in this regard and it was found that the Parliamentary Affairs Minister had not been consulted. Therefore Shri Kapoor's membership was unconstitutional.

The Central Government has taken over the management of the Central Yoga Research Institute and Vishwayatan Yoga Ashram on 25-5-77 through an ordinance. Inventory of goods is being made and it is a quite time consuming job and every file is being screened.

Yoga training programme is being simplified. The instructors have been directed to be more courteous. There has been marked improvement in the functioning of these institutions after the take over and as a result more persons are now coming there. It has been decided to carry on the research work on scientific basis.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दो योग सोसाइटियों के उपक्रमों का लोकहित में और उनका समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीमित अवधि के लिए प्रबन्ध ग्रहण का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया।
Clause 2 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : खंड 3 के लिए 2 संशोधन हैं। एक श्री राजगोपाल नायडू का और दूसरा श्री कपूर का। श्री कपूर यहां नहीं हैं इसलिए मैं खंड 3 से 16 एक साथ प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 से 16 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 3 से 16 विधेयक में जोड़े गये।
Clause 3 to 16 were added to the Bill.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गय।
Clause 1, the enacting formula and the Title were added to the Bill.

Sh. Raj Narain : I beg to move :

"That the Bill be passed."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

Sh. Raj Narain : I congratulate the opposition that they are satisfied with our arguments.

अनुदानों की माँगें, 1977–78
DEMANDS FOR GRANTS, 1977—78

वाणिज्य मंत्रालय तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब हम वाणिज्य मंत्रालय, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों पर विचार करेंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : महोदय, वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिवेदन हमें अभी मिला है जबकि नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के प्रतिवेदन मिले ही नहीं हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। बोलने से पहले हमें उन का अध्ययन करना है। अब सामान्य प्रक्रिया यह है कि आप हमें कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याएं बताने के लिए कहें लेकिन जब कटौती प्रस्तावों की सूची ही प्रकाशित नहीं हुई तो हम कैसे कहें। आप अनुमति दें तो हम सोमवार को उन्हें औपचारिक रूप से पेश कर दें।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं है, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। हमारे भरसक प्रयत्न के बावजूद प्रतिवेदन मिलने में विलम्ब हुआ है। उसके लिए खेद है। आशा है भविष्य में ऐसा विलम्ब नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब वाणिज्य मंत्रालय की मांग संख्या 15 और 16 और नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय की मांग संख्या 13 और 14 पर विचार करेगी। जिसके लिए 8 घंटे आवंटित किये गये हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : महोदय यह महत्वपूर्ण मंत्रालय भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय और नागरिक पूर्ति को मिला कर बनाया गया है। इसके लिए अधिक समय आवंटित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आवश्यक हो तो हम समय बढ़ा सकते हैं। आप को कितना समय चाहिये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : हम अभी समय बताने की स्थिति में नहीं हैं। हम उन्हें सोमवार को पेश कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह स्वीकार करता हूं।

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : महोदय चूंकि समय केवल 8 घंटे रखा गया है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि सदस्यों को अधिक समय देने के लिए पहले उनके भाषणों को सुना जाये। मैं अंत में बोलूंगा।

श्री टी० ए० पाई (उद्दीपी) : मैं प्रतिपक्ष की ओर से अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं तथा वाणिज्य मंत्री के अनुरोध करता हूं कि वह हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझावों पर पूर्ण गंभीरता के साथ विचार करें। यह हमारे लिए काफी संतोष की बात है कि गत-तीन चार वर्षों के दौरान हमारे देश द्वारा काफी अच्छा निर्यात किया गया। अब समय आ गया है जबकि हमें निर्यात के इस स्तर को बनाये रखना होगा। कुछ लोगों की मान्यता है कि निर्यात में विकास के लिए हमें विश्व बैंक ने प्रेरित किया है परन्तु वस्तुस्थिति इससे भिन्न है। विकासशील देशों ने विकसित देशों का काफी अधिक ऋण देना है तथा इस ऋण की धनराशि पांच वर्षों में दुगनी हो जाती है। विश्व के तेल संकट के बाद तो इस ऋण की राशि और अधिक बढ़ गई है। हमारे देश ने लगभग 750 करोड़ रुपया पश्चिमी या समाजवादी देशों का ऋण के रूप में देना है। अतः हमें इसके लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करनी होगी। इसलिए हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम निर्यात का वर्तमान स्तर बनाये रखें।

गत दो तीन वर्षों से ही देश की सम्पूर्ण स्थापित क्षमता का उपयोग किया जाने लगा है। कुछ समय तक हम केवल 40–50 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग करते रहे हैं। हमारे देश का यह भी दुर्भाग्य रहा कि हम अपने सम्पूर्ण उत्पादन की उचित खपत कर सकने में असमर्थ रहे। अब हमने निर्यात की ओर अधिक ध्यान देना आरम्भ कर दिया है। उदाहरणार्थ वर्ष 1972 में हमने 180 करोड़ रुपये के मूल्य के इंजीनियरिंग सामान का निर्यात किया। हमने यह भी कहा था कि 1978-79 या 1980 में देश लगभग 1000 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात करने में समर्थ हो जायेगा। यह संतोष की बात है कि भारी इंजीनियरिंग उत्पादों के कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत की अपेक्षा 20 प्रतिशत का निर्यात किया जाने लगा है।

अभी हाल ही में हमारे विदेश व्यापार में व्यापक परिवर्तन किये गये हैं। परम्परागत जूट तथा कपड़े का निर्यात करने के साथ-साथ अब हमारे इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं भारत अब केवल आधुनिक उत्पादों का निर्यात ही नहीं कर रहा अपितु भारत ने पहली बार विकासशील देशों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं के सामान का निर्यात भी किया है। हमने इंजीनियरिंग के सामान की विश्व मण्डी में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है । आज हमारे कारीगरों तथा उनकी तकनीक की विदेशों में कदर हो रही है।

हमारे देश की योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि हम बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ही अपने पुराने सिद्धांतों में परिवर्तन कर लें। जब हमने महत्वपूर्ण परियोजनाओं के सामान के निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश किया तो हमें यह देखने को मिला कि हमें अपने उद्योगों में केवल गतिशीलता ही नहीं लानी है, अपितु हमें अपनी वित्तीय संस्थाओं की पद्धति को भी गतिशील बनाना है।

जहां तक विदेशों में संयुक्त परियोजनाओं का सम्बन्ध है उनमें इसलिए हानि हुई है क्योंकि हम उनमें आने वाली कठिनाइयों का पता नहीं लगा पाते हैं और उनमें तभी घाटा होता है जब उन्हें विदेशों में ले जाया जाता है। सरकारी प्रक्रियाओं तथा अन्य कठिनाइयों के कारण जो उनमें बनाई जाती है, विदेशों में उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करना कठिन हो जाता है। यदि हमें वास्तव में ऐसी परियोचनाओं के विकास में रुचि है तो हमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास की विशेष क्षमताओं के साथ विदेशों में शीघ्र अपनी परियोजनाएं स्थापित करनी चाहिएं तभी भारत को दीर्घगामी लाभ हो सकेगा।

वाणिज्य मंत्री को यह नहीं मान लेना चाहिए कि निर्यात काफी है। सामान मात्रा का निर्यात करने से कहीं अधिक इसका गहरा महत्व होगा। हमें अपनी प्रतिभा का निर्यात करना चाहिए। हमें समस्त विश्व को और निकट करना चाहिए और विकासशील देशों में भागीदार बनाना चाहिए।

आज सम्पादन निर्यात को भारी उद्योगों से समर्थन मिला है। भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड में बिजली संयंत्रों का उत्पादन करने की हमारी योग्यता से ही विश्व में हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हमने कुवैत में 2500 मकानों का निर्माण कार्य अपने हाथों में लिया है। यदि हमारी ऐसी योग्यता न होती तो कोई हमारा विश्वास नहीं करता। अतः हमें अपनी इस योग्यता का अनवरत विकास और सुधार करना चाहिए ताकि हम विश्व व्यापार में भागीदार बन सकें।

यदि वाणिज्य मंत्री उन वस्तुओं की सूचियां देखें जो हमारे निर्यात कार्यक्रम में हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि उन्हें इस बात का पता लगाने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी कि एक विशेष वस्तु जो गत वर्ष निर्यात सूची में थी वह इस वर्ष की निर्यात सूची में नहीं है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि नहीं हो सकती।

हमें विश्व मण्डियों की दृष्टि से भविष्य में मण्डियों या क्षेत्रों का पता लगाना होगा। यह विचार कि जिस वस्तु को हम अपने देश के भीतर नहीं बेच सकते उसे सम्भवतः विदेशों में बेच सकते हैं, अत्यन्त उपहासास्पद विचार है। हमें यह पता लगाना होगा कि विश्व की भावी मांग क्या है।

यह विचार सही नहीं है कि व्यापार, आयात किए बिना निर्यात मात्र से ही बढ़ जायेगा। क्योंकि कोई देश हमसे सामान खरीदकर अपना काम नहीं चला सकता जब तक कि हम उसके बदले में उससे कुछ खरीदने के लिए तैयार नहीं हो जाते । अतः अब मंत्री महोदय को यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि क्या द्विपक्षीय व्यापार बहुपक्षी व्यापार बन सकता है। पूर्व यूरोपीय ब्लाक के साथ हमारा घनिष्ठ सहयोग बना है, जो कि दीर्घ अवधि से हमारा व्यापार भागीदार रहा है। उसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते।

यह खेद की बात है कि इसी एक मंत्रालय के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम, व्यापार विकास प्राधिकरण तथा अन्य बहुत से बहुउद्देशीय संगठन विदेशों में कार्य कर रहे हैं जो कभी-कभी एक दूसरे के हितों के प्रतिकूल कार्य करत हैं। देश को इस कारण बहुत अधिक हानि हुई है। वाणिज्य मंत्री को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने वाणिज्य दूत, राज्य व्यापार निगम, खनिज धातु व्यापार निगम, टी०डी०ए० आदि जिनके लिए बहुत सा रुपया मांगा है, के कार्य की जांच करनी चाहिये।

एक अन्य प्रश्न जिस पर सावधानी से विचार करना है वह है मुद्रास्फीति मूल्यों के बढ़ने से एक बड़ी जनसंख्या को हानि पहुंची है। मूल्यों के स्थिरीकरण में सभी वर्गों और दलों के हित निहित हैं। यह तभी संभव है जब हमारे पास यह जानने के लिए एक सुगठित तंत्र हो कि किस भाग में कौन सी वस्तु की कमी है। इसमें हम "समाचार" की सहायता ले सकते हैं। उसके संवाददाता देश के विभिन्न भागों से सरकार को यह सूचना दे सकते हैं कि वस्तुस्थिति क्या है तथा उसके आधार पर आवश्यक वस्तुएं यदि तुरन्त पहुंचा दी जाएं तो जमाखोरी और चोरबाजारी भी कम हो जाएगी।

सरकारी वितरण प्रणाली में उत्पादक को उचित मूल्य देने के साथ यह भी देखना होगा कि उपभोक्ता को भी उचित मूल्य पर सामान मिले। ये दोनों उद्देश्य तभी प्राप्त किए जा सकत हैं जब उत्पादक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य के अन्तर को कम किया जाए।

यह जानने पर बड़ा धक्का लगा है कि गेहूं खाने वालों को 24.15 रु० प्रति क्विन्टल की छूट दी जाती है जबकि चावल खानेवालों को केवल 1.35 रुपए प्रति क्विन्टल। यह भेद भाव क्यों? दोनों को बराबर छूट दी जानी चाहिए।

विभिन्न मंत्रालयों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है। इस समय खाद्य विभाग वाणिज्य मंत्री के पास नहीं है। उसके पास वनस्पति घी या चीनी उद्योग भी नहीं है। अतः उसे अन्य मंत्रियों से बात करके समन्वय लाना होता है और जब तक यह सब होता है तब तक मूल्य बढ़ जाते हैं तथा उन्हें कम करना उनके लिए कठिन हो जाता है। अतः मंत्रालयों का पुनर्गठन आवश्यक है ।

शहरों में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। एक और निगम बनाने के सरकार के सुझाव से समस्या हल नहीं होगी। असल कठिनाई गांव से शहरों को सब्जी लाने की है। यदि हम परिवहन की व्यवस्था कर सकें तो शहरों में जीवन और आकर्षक हो जाएगा तथा सब्जी उगाना गांव वालों के लिए और लाभप्रद हो जाएगा।

श्री आर० के० अफने (सुन्दर नगर) : मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं क्योंकि उन्हें पिछली सरकार से विरासत में एक अव्यवस्थित मंत्रालय मिला है। मंत्री महोदय को अव्यवस्थित स्थिति का सामना हिम्मत से करना चाहिये।

[श्री सोनुसिंह पाटिल पीठासीन हुए]
[Shri Sanu Singh Patil in the Chair]

हम कीमतों में वृद्धि के बारे में बहुत चिंतित हैं। इसके बारे में विभिन्न सदस्यों के विभिन्न विचार हैं। विरोधी दल मूल्य वृद्धि के मामले में निराधार भविष्यवाणी कर रहे हैं। मंत्री महोदय को इनकी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिये और हिम्मत से काम लेना चाहिये।

अक्तूबर, 1976 में यह स्पष्ट हो गया था कि पाइपलाइन में खाद्य तेल बहुत कम है और पिछले कई वर्षों से हमारा स्टाक भी सबसे कम है। उस समय सरकार को खाद्य तेलों का आयात करना चाहिये, परन्तु बड़े खेद की बात है कि देश में खाद्य तेलों की कमी होने पर कांग्रेस सरकार ने उनका आयात करने के बजाय उसके निर्यात की अनुमति दे दी। यदि वे सस्ता सोयाबीन का तेल भी खरीद लेते तो सम्भवतः हमारी समस्या कुछ हद तक आसान हो जाती परन्तु ऐसा नहीं किया गया। जनवरी-फरवरी, 1977 में स्थिति बहुत नाजुक होने पर उन्होंने बिना किसी शर्त के 500 करोड़ के लाइसेंस आयातकों को दिये। जिन लोगों को लाइसेंस मिले उन्होंने तेल खरीद कर बेच दिया क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल का मूल्य बढ़ गया था। कुछ लोग उसे यहां ले आये और उन्हें उस पर बहुत अधिक लाभ भी मिला। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं कि यहां आने पर प्रति टिन तेल का मूल्य 110 रुपये पड़ा और 15 दिन बाद उन्होंने उसे 137 रुपये प्रति टिन के भाव से बेचा जिससे उन्हें 20 से 22 प्रतिशत का लाभ हुआ। इसकी जांच की जानी चाहिये।

मेरे मित्र श्री पाई ने निर्यात नीति का उल्लेख किया है। पिछली सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आ रहे परिवर्तन को समय पर कभी नहीं समझा। उस समय देश में मुद्रास्फीति थी। अब आयातक देशों में मुद्रास्फीति की स्थिति नहीं है। उस समय आपने निर्यात को बढ़ावा देने की नीति अपनाई और आयात पर नियंत्रण लगाये। 1973 के बाद स्थिति काफी बदल गई है। पिछली सरकार ने इन बातों को ध्यान में नहीं रखा। माननीय मंत्री आयात-निर्यात नीति में अमूल परिवर्तन करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखें। 1973 के बाद अमरीका और यूरोपीय देशों के पास डालर का भण्डार नहीं हो रहा था। व्यापार का रुख ही बदल गया था। अब डालर तेल निर्यातक देशों में इकट्ठा होने लगा है। अतः इन सब बातों को आयात अथवा निर्यात पर नियंत्रण लगाते समय ध्यान में रखा जाये। विश्व भर में विनिमय की दर निश्चित कर दी गई थी। पर अब इसे स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। इसी कारण तस्करी घट गई है। सरकार की नीति या आपात स्थिति के कारण तस्करी नहीं घटी। यह इस कारण कम हुई है कि काले बाज़ार की दर में और सरकारी विनिमय दर में बहुत कम अन्तर है। इसी कारण उनके लिये तस्करी करना लाभदायक नहीं है। पहले एक औंस सोने का मूल्य 35 डालर था। उस समय इस देश में सोने का मूल्य काफी ऊंचा था और उसी कारण उसकी देश में तस्करी होती थी। अब सोने का मूल्य निर्धारित नहीं है। यह मांग तथा सप्लाई स्थिति पर निर्भर करता है। इसी कारण इसका मूल्य विदेशों में बहुत अधिक और अन्तर कम होने के कारण इसकी अब तस्करी नहीं होती।

इस समय निर्यात संवर्धन नीति को पूरी तरह बदलने की अत्यधिक आवश्यकता है, निर्यात स्वयं ही होगा, क्योंकि हमारे रुपये की कीमत उसके मूल्य से ज्यादा नहीं है जैसा कि पहले था। जब रुपये की कीमत उसके मूल्य से ज्यादा थी तो उसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता थी, अब नहीं है। परिवर्तित स्थिति में भी हम पुरानी प्रणाली को अपनाये हुए हैं। मंत्री महोदय को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल ही निर्यात संवर्धन नीति में परिवर्तन करें। निर्धारित विनिमय दर के उपयुक्त समूचे तंत्र को बदल दिया जाना चाहिये और वर्तमान में स्वतंत्र विनिमय दर के अनुकूल ही तंत्र की स्थापना की जानी चाहिये।

एक अन्य प्रश्न रुग्ण मिलों, विशेषकर रुग्ण कपड़ा मिलों का है। सम्भवतः इस उद्योग पर सबसे अधिक नियंत्रणों का शिकंजा रहा। इन्हें जितनी जल्दी समाप्त किया जा सके उतना अच्छा है। एक

बहुरेशा नीति का बनाया जाना ही उचित है। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि रूई नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के अन्तर्गत है और रेशा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन। यदि दोनों मंत्रालयों में समन्वय नहीं होता तो इससे उद्योग के विकास में अनेकों समस्याएं उठ खड़ी होंगी ।

इस सम्बन्ध में इस बात पर ध्यान दिया जाये कि मानव निर्मित रेशे के कपड़े का निर्यात कठिनाई से 30 करोड़ रुपये का हुआ जबकि दक्षिणी कोरिया ने 2000 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया और ताइवान ने 1200 करोड़ रुपये का। अतः हमें यह देखना है कि संगठित क्षेत्र में मानव निर्मित रेशे का निर्यात बढ़े और इसके लिये हमें रेशे के आयात के लिये प्रोत्साहन देना होगा। हमें इससे कोई हानि नहीं होगी क्योंकि हम कच्चे माल का आयात करेंगे और तैयार माल का निर्यात। मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिये। पिछली सरकार ने 400 करोड़ रुपये की रूई का आयात करने के आदेश दिये थे। यदि यह आयात की जाती है तो इसका उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मंत्री महोदय ऐसी नीति अपनायें जिससे अधिक से अधिक मानव निर्मित रेशे का आयात हो और रूई उत्पादकों की पूरी सहायता की जा सके।

रुग्ण मिलों को अपने हाथ में लेने पर हमें लाभ नहीं हुआ। राष्ट्रीय कपड़ा निगम को बड़ी हानि हो रही है और उन्होंने और अधिक मिलों को अपने हाथों में न लेने की घोषणा की है। एक अन्य सुझाव यह दिया गया है कि अच्छे मिल इन मिलों को ले लें। यह विकल्प भी उचित नहीं है क्योंकि इसका अर्थ रुग्ण मिलों की सरकारी धन से सहायता करनी ही है। फिर यह भी पता नहीं चल पायेगा कि रुग्ण मिल अब अच्छी हालत में आ गया है या नहीं, क्योंकि उसके साथ स्वस्थ मिल भी रहेगा। अतः तीसरे विकल्प को स्वीकार किया जाये। बहुत अधिक घाटा होने की आशंका पर प्रबन्धक जब मिल बन्द करने का फैसला करें तो उसे नीलाम कर देना चाहिये। नया प्रबन्ध बिना किसी भार के उसे ग्रहण करे।

खनिज व धातु व्यापार निगम को व्यापारिक रूप से कार्य करना चाहिये। आप अन्तर्राष्ट्रीय क्रयादेशों के बारे में सरकारी विभाग की तरह कार्यवाही नहीं कर सकते। आपने राज्य व्यापार निगम की मशीनरी में कुछ हद तक सुधार तो किया है पर खनिज व धातु व्यापार निगम की मशीनरी को नहीं सुधारा है। आपको इसकी मशीनरी में सुधार करने के लिये कुछ न कुछ कार्यवाही करनी होगी। केवल व्यापारिक कम्पनियों ने ही भारी लाभ कमाया है। यह वास्तविक लाभ नहीं है, यह एकाधिकारी लाभ है। मंत्री महोदय व्यापारिक कम्पनियों को लाभ कमाने की क्षमता को देखकर अपना विचार न बनायें। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उचित कार्यवाही करेंगे ताकि तेल, कपास, सीमेंट तथा अन्य अभाव की वस्तुओं की सप्लाई सम्बन्धी व्यवस्था ऐसी हो जिससे जनता सन्तुष्ट हो।

Chaudhury Brahm Parkash (Outer Delhi): A question has been raised whether there should be monopoly in the country; and if so, whose and what type of monopoly there should be. I would like to say that the State should have complete monopoly over trade and industry. The Minister of Commerce should provide for the maximum expansion of the State sector wherever it is possible.

The Ministry of Commerce is responsible for creation of black money in the country, and, therefore until the entire structure is changed, there will not be much improvement in the elimination of corruption in the administration. It needs a complete overhauling.

The present condition of cooperatives in the country is that they have been reduced to official agencies only. The cooperative movement has now become an official movement. It will have been better if a corporation is set up with the direct responsibility of the government. On paper, a cooperative is called voluntary people's organisation, but in actual practice it remains neither official nor non-official.

As regards civil supplies, we do not pay adequate attention to fulfil the requirements of rural people. The Vaikunth Bhai Mehta Committee has recommended the de-centralisation of administration on cooperative principles. Two different departments were created to look after community development and cooperation. There was a report recommending de-officialisation of the cooperative movement.

A question has been repeatedly raised as to whether there should be large or small village societies. Though the Credit Survey Committee had recommended formation of large-sized societies, yet this question had been raised several times. It was turned down on the ground that in the name of efficiency, they do not want to do away with cooperative principles. Today, the large scale societies are the order of the day. Therefore, this matter has to be reviewed with a new approach. A working group should undertake the study of all reports and suggest the changes and investments to be made in the structure of cooperative societies. Concrete measures should be taken to review the cooperatives in our economic system.

Shrimati Ahilya P. Rangnekar (Bombay North-Central) : The present position in regard to supply of cereals and the export is the result of the pattern of trade that had been followed during the last few years. I do not agree with the proposition that if we do not export, we will perish. This argument is wrong that we should resort to export because our purchasing power is going down. Our economy depends on external loans with various conditions attached to them. As a result we have to export various raw materials that we need very much for our domestic requirements. This causes a great pressure on our economic structure. The money which we receive from Western Countries in the form of loan, creats difficulties in our economy, for there are always some sling attached to it. Due to it we have to export bulk of raw material to those Countries, which we badly nedeed in our Country itself. Till we are depend of foreign loan, we can't get rid of this vicious circle and we can't improve our economy.

One Hon. member of opposition said that this Government is exporting much less than the previous Government. I can probe that the factual position is quite different. For example in the year 1976-77 the target of export of stainless steel, embroidered fabrics, hand knitting machines etc. was fixed of the worth of rupees 500 lakhs, but they could export only of rupees 341 lakhs. But this Government have fixed the target of rupee 1000 lakhs. It means the target has just doubled. But there should be drastic cut in the export by some commodities.

Today a number of factories, jute mills and textile mills are closed. The textile mills which are under your control are not functioning properly. 6 more mills are likely to close down. The high officials in the National Textile Corporation should be replaced with efficient and able personnel.

Recently you took over Kohinoor mill after paying a compensation of Rs. 15 crores. But the workers have not been paid their wages. This Corporation is not properly functioning. There is wide-spread corruption in this Corporation. My suggestion is that the entire textile industry should be nationalized other-wise there are very little chances of improving this body.

So far as Civil Supplies are concerned the prices are going up. It should be noted that the figures furnished by the Minister are only up to the month of January whereas the prices are continuously increasing.

In a meeting held on the 7th of this month you appealed to the traders and the industrialists to keep price line down, but I think nothing has happened. Simply by giving warning to them will not do. You will have to take concrete steps in this regard. There is black-marketing in the field of edible oil. Edible oils should be imported through S.TC.

In the year 1975 the per Capita consumption of sugar was 6.1 Kilogram, but in 1976-77 there has been considerable decline in it. Even then you are going on exporting sugar and that too on subsidy rates. Although our sugar production has gone up, but there has been no fall in its price. The result is that the producers as well as Consumers are suffering.

Fortunately you have stopped the export of onion. Before that there was 64 per cent increase in its price and the middle were earning huge profits.

It is not right to say that by paying workers their dues prices go up. It is evident from this point that last year you did not pay the workers Rs.1500 crores, but the prices constantly went up. So there is not relation between the wages of workers and prices. 75 per cent people are under poverty line.

You should have constant watch over the activities of the traders and smugglers. If the Government fail to reduce the prices, the women of this country would be forced to protest against it.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : निवर्तमान सरकार द्वारा आरम्भ किये गये निर्यात संवर्धन कार्यक्रम को इस सरकार को चालू रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी अर्थ व्यवस्था में सुधार हो।

निर्यात को आर्थिक सहायता देने के लिए इस बजट में भारी धन की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए चीनी के मामले में सहायता देने हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वर्तमान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय उपभोक्ताओं को इस भारी आर्थिक सहायता का बोझ न उठाना पड़े जो कि निर्यातकों को दी जा रही है। इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

सरकार को भारतीय माल की खपत के लिए विदेशों में, विशेषतया मध्य पूर्व और यूरोपियन देशों में मंडियों की खोज करनी चाहिए। यह ध्यान रखा जाये कि हाल के वर्षों में इन देशों के लिए आयात बहुत बढ़ गया है। लेकिन इसका लाभ ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और अमरीका ने ही उठाया है।

हमें पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में वाणिज्यिक आसूचना रखनी चाहिए। इससे हमें तेल उत्पादक देशों में संयुक्त उपक्रम के लिए अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। कुछ दक्षिणी राज्य खाल और चमड़ा जैसे कच्चे माल का निर्यात कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इन वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इस प्रयोजन के लिए सरकारी क्षेत्र में एक विशेष एकक खोलना चाहिए जिससे वह दक्षिणी राज्यों के विभिन्न भागों से खाल और चमड़ा एकत्र करे और यह देखे कि तैयार माल का निर्यात हो।

सहकारिता प्रणाली उचित कार्य नहीं कर रही है। सहकारिता प्रणाली के स्थान पर सहकारी पूंजीवाद कार्य करने लगा है। सहकारिता के क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जायें कि हमारे लोगों में वास्तविक सहकारिता की भावना पैदा हो। सहकारी विधान में जो त्रुटियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए और देश में सहकारी आन्दोलन को मजबूत करने तथा उसका पूर्ण पुनर्गठन करने की आवश्यकता हो।

हाल ही में प्रधान मंत्री ने व्यापारियों, जमाखोरों और चोर बाजारियों से मूल्य स्तर बनाए रखने की अपील की है। ये वही लोग हैं जो देश को नष्ट करना चाहते थे। क्या इन पर प्रधान मंत्री की अपील का कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या इस अपील का कोई परिणाम निकला है? इसके विपरीत आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं और अब भी बढ़ रहे हैं। मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए कारगर कदम उठाये जाने चाहिएं।

कर्नाटक में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कई बार मांग की गई कि इस राज्य में एक नारियल बोर्ड स्थापित किया जाये। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह उत्पादकों को लाभकर मूल्य देना सुनिश्चित करें।

Shri Paramanand Govindjiwala (Khandwa): The Consumers have a number of pr o - blems and we have to find out their solutions. A policy was framed in the year 1966 t o provide consumers essential commodities at reasonable prices. The aim of that policy w a to supply essential commodities to the consumers at reasonable prices through Consumers Cooperative Committees. Now the question is whether we have been successful to solve the problems of Consumers through these Cooperative Societies ? The conditions of most of the Cooperative Societies is miserable. We should find out the cause of their failure. The main reason is that these societies could not understand the conduct and nature of our people. At the initial stage our people extend full cooperation, but they do not extend their cooperation for ever.

Hon. Minister want to open Janata Shops in our rural areas so that the consumers could get essential commodities at reasonable prices. Whether these shops would be allowed to supply commodities on credit ? Unless they are allowed to supply commodities on credit, such programmes cannot be successful, because our people in rural areas are not in a position to purchase things of their daily requirement in cash.

It should be ensured that these Janata Shops do not become victims of beaurocracy.

There is no coordination among different departments. A Tobacco Board has been constituted under this Ministry which would find out chances for its export. There are lakhs of people of Indian origin in foreign countries and they use commodities made of tobacco in India. We should find out international markets so that we may export it in large quantities. Under the rule 28 of Food Adultration Act it has been stated which colours can be used in food articles. Under rule 29 names of the food articles are enumerated in which different tobacco colours are used. This colour can be utilised in ice cream, milk, coca cola and other soft drinks as well as in liquor. As a result it is becoming a big source of corruption. These food officers are the most corrupt people and this Act itself is responsible for corruption.

I will like to say something about powerlooms. Powerloom has been exempted from compound levy, but if a powerloom manufactures cloth from the yarn purchased from composite mill, it will have to pay duty. So the net result of this would be that finished products manufactured by powerlooms would be subjected to an excise duty higher than the product of a composite mill. Therefore, this needed to be reconsidered otherwise cloth manufactured by powerlooms will be costlier than the mill cloth. Such thing happened only when there is lack of coordination between different departments. Steps should be taken to achieve complete coordination among various ministries and departments of the Central Government.

We have to protect the interest of the weaker section. In 1966-67 a Committee was constituted under the chairmanship of Sh. Ashoka Mehta. Its report is still a valid document. We should try to implements its recommendations.

श्री के० सूर्यनारायण (एलुरू) : वित्त मंत्री ने ग्रामीण जनता की सहायता और कृषि का विकास करने की इच्छा व्यक्त की है । कृषि के बाद सबसे अधिक जनसंख्या बुनाई कार्य में लगी हुई है लेकिन शक्तिचालित करघों को दी गई रियायतों के कारण हथकरघे क्षेत्र को दी गई रियायतें निष्फल हो गई हैं। इस मामले पर पुनर्विचार की जरूरत है क्योंकि 90 प्रतिशत हथकरघे या तो सहकारी समितियां चला रही हैं अथवा बरीब व्यक्ति उनमें लगे हुए हैं । इसके विपरीत शक्तिचालित करघे तो अमीर व्यक्तियों के ही हैं।

हमारे देश में साधारण करघों की सख्या 2 करोड़ है और उन पर 40,000 परिवार निर्भर करते हैं। अधिकांश हथकरघा बुनकर मुसलमान ही हैं या फिर वे हरिजन हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाये।

कांग्रेस सरकार ने बुनकरों के कल्याण के लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनाईं थीं। यदि सरकार बुनकरों की सहायता करना चाहती है तो उन योजनाओं को पूरा किया जाना चाहिये। धागे पर कुछ रियायत दी जाये और वह सीधा बुनकरों को ही दिया जाये।

जहां तक सहकारी आंदोलन का सम्बन्ध है भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारें या सहकारी सस्थानों को दी गई धनराशि का पर्यवेक्षण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। हमें सहकारी समितियों को दिये गये ऋण पर ब्याज लेने में ही रुचि नहीं रखनी चाहिये लेकिन यह सुनिश्चित करना हमारा कर्त्तव्य होना चाहिये कि उत्पादन बढ़े और सहकारी आंदोलन सुदृढ़ हो तथा इसका पर्याप्त विस्तार हो। उन सभी सहकारी समितियों तथा अन्य संगठनों के उपर एक नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण हो जिन्हें ऋण दिया जाता है।

1976-77 के प्रतिवेदन के अनुसार 744 चावल मिलों से 721 चावल मिलें लगाई जा चुकी हैं और 180 चीनी के कारखानों में से 160 चीनी मिलों को लाइसेंस दिये गये हैं । परन्तु महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ कर अन्य सभी जगहों पर सहकारी चीनी मिलें ठीक कार्य नहीं कर रही हैं वहां नियमों और हिदायतों का पालन नहीं किया जाता। अखिल भारतीय सहकारी सम्मेलन में यह संकल्प पास किया गया था कि आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में सहकारी कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिये। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ नहीं हुआ है। निहित स्वार्थ पैदा हो गये हैं और सहकारी आंदोलन का विरोध करने वाले लोग इस क्षेत्र में घुस गये हैं। इसके फलस्वरूप सहकारी समितियां सुनियोजित, ढंग से काम नहीं कर रही हैं। जब तक हम इन सहकारी समितियों के बारे में ठोस कदम नहीं उठायेंगे वे समितियां आगे नहीं चल सकतीं।

गांवों में रहने वाली 80 प्रतिशत जनता किसान है। इसमें से 60-70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं । थोड़े से 5-10 प्रतिशत लोग बुनकर हैं और 10 प्रतिशत बढ़ई तथा अन्य कारीगर हैं। राष्ट्रीय विकास निगम ने इनके लाभ के लिए सहकारी विपणन तथा संसाधन एकक, खाद्यान्न विपणन संसाधन एकक, गन्ना संसाधन एकक आदि 15 संगठन बनाये हैं। हमें यह देखना चाहिये कि ये सभी सहकारी एकक ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में सरकार ने सहकारी चावल मिलों को चलाने के लिए न तो उन्हें कोई प्राथमिकता दी है और न ही समय पर आवश्यक सहायता प्रदान की। एक तो सभी सहकारी चावल मिलें बेकार पड़ी हैं और दूसरी ओर भारतीय खाद्य निगम नई चावल मिलों का निर्माण कर रहा है । वह नई मिलों के निर्माण की बजाय इन मिलों को पट्टे पर क्यों नहीं ले लेते या सीधे खरीद ही क्यों नहीं लेते। भारतीय खाद्य निगम एक सरकारी संस्थान है और सहकारी समितियों में भी सरकारी धन होता है। आन्ध्र प्रदेश को चाहिये कि मिलों को बेकार रखने के बजाये पट्टे पर दे देना चाहिये या बेच देना चाहिये।

खुली बिक्री और लेवी चीनी को 35 प्रतिशत और 65 प्रतिशत की दोहरी नीति को त्याग देना चाहिये। 35 प्रतिशत चीनी की खुली बिक्री की अनुमति देकर सरकार काले बाजार को बढ़ावा दे रही है। सरकार या तो पूरा नियंत्रण रखे या चीनी की बिल्कुल खुली बिक्री होनी चाहिये।

चीनी उद्योग में उत्पाद शुल्क घटाने की आवश्यकता है। यदि सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही तो उत्पाद शुल्क घटा ही दिया जाना चाहिये। यदि सहकारी मिलें ठीक से नहीं चल रहीं हो उसका कारण प्रबन्ध व्यवस्था का दोषपूर्ण होना या निदेशकों द्वारा गलती करना है। आप उस त्रुटि को दूर करिये। सहकारी आंदोलन को बचा कर ही ग्रामीण क्षेत्र को उन्नत किया जा सकता है।

Shri Anant Dave (Kutch) : Sir, I support the Demands presented by the hon'ble Minister. But I have to say one or two things. Kandla Free Trade Zone has been in existence for the last 12 years and it consists of 28 units. Still it was distressing that no law has been enacted for this zone and this zone is working on the basis of notification only.

This Zone earns valuable foreign exchange for the country and in 1977-78 we hope to earn foreign exchange equivalent to Rs. 500 crores yet we have earmarked Rs. 1 lakh for its development and construction works. This is a very meagre amount. It should be enhanced.

So far the Government has not appointed appraiser for this free zone and the business-men who come for their business have to experience lot of difficulty on this account. The post should be filled up.

There are heaps of waste material and no rules have been framed for their disposal. In this connection I have written to the hon'ble Minister also. Lastly, I hope the hon. Minister will look into the problems of this area and at the same time I support the demands presented by him.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : (अहमदनगर) : मैं मुख्य रूप से सहकारिता के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा परन्तु उससे पूर्व मैं वाणिज्य मंत्रालय के बारे में एक दो बातें करना चाहूंगा ।

जहां तक देश के निर्यात का संबंध है उसके संबंध में तो मेरी राय यही है कि निर्यात के लिये यदि हमें कुछ त्याग भी करना पड़े तो हमें उसके लिये तैयार रहना चाहिये । हमें सदा यह बात दृष्टिगत रखनी चाहिये कि अन्ततः मूल्य की स्थिरता में ही रुपये की स्थिरता निर्भर करती है । इस संदर्भ में जर्मनी तथा जापान के उदाहरण काफ़ी सशक्त हैं । श्रीमती अहिल्या रंगनेकर ने चर्चा के दौरान यह प्रश्न उठाया है कि चावल का निर्यात क्यों किया जाता है ? चावल का निर्यात यदि अपने देश की विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार करने के लिये किया जाता है तो भला इसमें क्या बुराई है । इसीलिये मेरी मान्यता तो यह है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार करने की दृष्टि से हमें सदा त्याग की भावना से कार्य करना चाहिये ।

हमारे देश द्वारा खली का निर्यात भी किया जाता है । मेरी मान्यता यह है कि हमें खली का निर्यात नहीं करना चाहिये क्योंकि जब आप देश में डेरी उद्योग तथा पशुपालन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो खली आदि को उचित मूल्यों पर उपयुक्त मात्रा में देश में उपलब्ध करवाया जाना चाहिये । यह अच्छी बात है कि इस समय हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति कुछ संतोषजनक है । अतः परिस्थितियों में खली का निर्यात यदि बन्द किया जाता है तो संभवतः उससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तथा लोगों को रोजगार भी मिलेगा ।

मेरा अन्य निवेदन यह है कि कृषि वस्तुओं का उपयोग विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये काफ़ी अच्छी तरह किया जा सकता है । हमारा यह भरसक प्रयत्न होना चाहिये कि निर्यात तथा स्वदेशी खपत के बीच उपयुक्त तारतम्य तथा समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये । कृषि वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिये । कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का निर्यात बन्द करने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि अन्ततः इससे किसानों को ही घाटा होने की संभावना है । फ़िर इसका असर मूल्य वृद्धि पर भी पड़ेगा तथा मूल्यों को नियंत्रण में रख पाना सरकार के लिये कठिन हो जायेगा ।

[श्री द्वारका नाथ तिवारी पीठासीन हुए
Shri D. N. Tiwari in the chair]

अब मैं अपने मुख्य विषय की ओर आता हूं । हमारे देश के वर्तमान सरकारी आन्दोलन में काफ़ी खामियां हैं कुछ लोगों ने यह मत भी व्यक्त किया है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ही

देश में सहकारिता का स्वच्छ विकास नहीं हो पाया है । परन्तु मेरी मान्यता यह है कि सहकारिता आन्दोलन के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा वर्गीकृत समाज की ही रही है । देश में जमीनदारी प्रथा के प्रचलन के कारण ही यह आन्दोलन सफलतापूर्वक विकसित नहीं हो पाया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसके उपयुक्त विकसित न होने का कारण यह है कि न तो वहां भूमि ही है तथा न ही उपयुक्त उर्वरक ही उपलब्ध है । भूमि सुधार नियमों के क्रियान्वयन का भी सहकारी आन्दोलन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है । मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब तक देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भूमि सुधार संबंधी कानूनों का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता, तब तक सहकारिता के पूर्ण सफलता की आशा नहीं की जा सकती ।

सहकारिता आन्दोलन की असफलता के लिये राजनीतिक कारणों की अपेक्षा सामाजिक कारण अधिक जिम्मेवार हैं । हमारे देश का सामाजिक ढांचा तो पुराने सामंतवाद पर ही आधारित है । अतः अब समय आ गया है जब कि हमें उसमें आधारभूत परिवर्तन कर उसे अपनी सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना होगा । अब हमें उसका प्रजातंत्रीकरण करना होगा ।

यह ठीक है कि देश में जो सहकारिता आन्दोलन चल रहा है उसमें अनेक त्रुटियां हैं परन्तु इसके बावजूद भी हमें देश में सहकारिता आन्दोलन की प्रगति की सराहना करनी पड़ेगी । वर्ष 1952 में यदि सहकारिताओं के माध्यम से देश में कृषक वर्ग को 25 करोड़ रुपये की धनराशि का वितरण किया गया तो इस समय सहकार संस्थाओं के माध्यम से वितरित की जा रही धनराशि 1200 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई है । हमें सहकारिता में अपना विश्वास बनाये रखना चाहिये । गुजरात तथा पंजाब में सहकारिता आन्दोलन ने काफ़ी सफलता प्राप्त की है । आज देश में लगभग 1500 करोड़ रुपये की कृषि वस्तुएं सहकारी समितियों के माध्यम से बेची जा रही हैं । आज आवश्यकता केवल इस बात की है कि हमें सहकारिता की त्रुटियों को दूर कर, इसे और कुशलता-पूर्वक चलाने का प्रयास करना चाहिये ।

जहां तक सहकारिता आन्दोलन में राजनीतिक हस्तक्षेप का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि सरकार ने सहकारिता आन्दोलन में काफी हस्तक्षेप किया हैं तथा कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को इस पाप से अलग नहीं रख पाया है, मैं अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि देश में सहकारिता आन्दोलन बिना सरकारी हस्तक्षेप के चल सके । यदि सहकारिता आन्दोलन को राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग न रखा गया तो इसका समुचित विकास नहीं हो पायेगा तथा यदि सहकारिता का उचित विकास न हुआ तो उसका नुकसान देश की गरीब जनता तथा देश की अर्थ-व्यवस्था को होगा । मेरी निजि मान्यता यह है कि जैसे ही कोई सहकारिता का कार्यकर्त्ता विधानसभा या संसद् का सदस्य चुन लिया जाता है है तो उसे तुरन्त ही सहकारिता आन्दोलन से अपना संबंध विच्छेद कर लेना चाहिये । सहकारी संस्थाओं के चुनाव पूर्णतया प्रजातांत्रिक ढंग से करवाये जाने चाहिये । सहकारिता की सदस्यता के लिये नामांकन का सिद्धांत अपनाना भी स्वस्थ परंपरा नहीं है ।

अब एक-आध शब्द मैं सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षण की विधि के बारे में भी कहना चाहता हूं । सहकारी संस्थाओं की वर्तमान लेखा परीक्षण विधि काफी दोषपूर्ण है । लेखा परीक्षण का कार्य कई बार एक या दो वर्ष के बाद होता है जब तक कि सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है । इससे उन्हें अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिये काफी समय मिल जाता है । अतः लेखा परीक्षण का कार्य सहकारिता वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद करवाया जाना चाहिये । यदि सम्भव हो सके तो हमें उसके लिये महालेखा परीक्षक जैसे स्वतन्त्र कार्यालय की

सांविधिक स्थापना करनी चाहिये । एक इस प्रकार की प्रणाली भी बनानी चाहिये जिससे कि राशि का दुर्विनियोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके । सरकार को सहकारिता के नीति संबंधी मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये तथा इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि धन का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सके।

श्रीमान जी, यह खेद की बात है कि अभी तक इस मंत्रालय का विभाजन नहीं किया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या कारण है । सहकारी ऋण ग्रामीण ऋण की परिधि में नहीं आता है यह तो कृषि मंत्रालय का ही एक भाग है परन्तु कृषि उत्पादों की सप्लाई इत्यादि का कार्य 'माफेड' तथा इस जैसे अन्य संगठनों द्वारा किया जाता है । कृषि उत्पादों की सप्लाई का कार्य भी कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत क्यों रखा गया है । मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि सहकारी संस्थाओं के लिये एक अलग मंत्रालय तथा अलग मंत्री होना चाहिये ।

देश में सहकारिता के विकास के लिये राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम एक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली संगठन है । इसमें हमें गैर-सरकारी सदस्यों को स्थान देना चाहिये । यदि हो सके तो इसके लिये वर्तमान कानून में उपयुक्त संशोधन भी कर देना चाहिये । हमें सहकारिता के विकास के लिये इस संगठन को अधिकाधिक अनुदान तथा ऋण देना चाहिये । इस निगम को यह अधिकार भी होना चाहिये कि वह बाजार से या अन्य उपयोगी संस्थाओं से ऋण ले सके।

मैं एक बार फिर यही कहना चाहता हूं कि सहकारिता को राजनीतिक प्रभाव से सदा मुक्त रखने का प्रयास किया जाना चाहिये । यदि सहकारिता में राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा तो वह नीतियों को क्रियान्विति करने में सफल नहीं हो पायेगी ।

कर्मचारियों को सौंपे गये कार्यों में दखल नहीं दिया जाना चाहिये । सहकारिता आन्दोलन के लिये राज्य अपने बजटों में अपर्याप्त प्रावधान रखते हैं । केन्द्रीय सरकार को इस बारे में राज्य सरकारों द्वारा पालन करने के लिये नीति निर्धारित करनी चाहिये ।

मेरे विचार में राज्यों को खाद्यान्न तथा अन्य अनिवार्य वस्तु लाने ले जाने के लिये किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगानी चाहिये । केन्द्रीय सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। अन्यथा स्थिति नियंत्रण में नहीं रहेगी ।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की अनुमति बिना राज्य सरकारों को कोई भी शक्तियां प्राप्त नहीं है । गुजरात सरकार को तेल के बीजों पर कोई पाबन्दी नहीं रखनी चाहिये ।

Shri Yuvraj (Katihar) : I support the demands for grant in respect of commerce Ministry. Jute is one of our main traditional item of export. It earns valuable foreign exchage for the country. During the last four to five years there had been deterioration in our jute industry. Foreign exchange earnings from this industry has been going down which has greatly harmed farmers of Bihar, West Bengal and Assam. The Jute Corporation was set up in 1973. There are about 90 centres of the corporation. This corporation has failed to purchase jute from cultivator as a result of which cultivators have to sell their jute to the industrialists who purchase it at the rate of 40-41 per maund whereas the Corporation has fixed the price at Rs. 55 per maund.

A big mill of Bihar, M/s R.B. H.M. Jute Mill has been closed and the poor workers are suffering. The industrial Development Commissioner of Bihar has written to the Central Government recommending that they should take over the management of the company under section 18A of the Industries (D and R) Act immediately and run the factory.

Some 35,000 workers are working in this mill. Their condition is pitiable. This has affected people of Purnea, Katihar and Saharsa. If the mill owner is not able to run the mill the Central Government should take over this mill and run it.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I support demands of grant in respect of Commerce Ministry. It is heartening to note that this year the balance of trade is going to be favourable whereas in 1975-76 there was a deficit of Rs. 1224 crores. The Minister deserves to be congratulated for the same.

The former Government had been exporting some commodities which are necessities of life. The result is that the prices of those commodities went up in the country and the people had to suffer. It is high time the export of necessary commodities, such as, pulses, vegetables, fish and oil cakes is stopped forthwith.

It is said in the Ministry's report that in 1977-78 sugar and cement will be exported. Since cement is in short supply in the country, it should not be exported.

Import duty on some commodities has been removed and as a result those commodities have been imported in large quantities. Consequently, the local manufacturers are suffering. There should be a balanced policy whereby our foreign exchange is utilised and there is no shortage of essential commodities and their prices also do not go up.

There is no doubt that provision for handloom has been more than doubled. But the question is whether this increased provision is enough in view of the policy of our party. The handloom weavers are facing a number of problems. If we really want to help them, more provision should be made for handloom in the Supplementary budget :

A huge stock of controlled cloth has accummulated in the cloth mills because the rural people who used this cloth do not have necessary purchasing capacity. So long as the purchasing capacity of the people is not built up, more production is not going to help them.

There are 63 trade missions functioning abroad over which an amount of Rs. 2½ crores is being spent by way of administrative expenses. But unfortunately, those missions do not pay much attention on trade and do not provide any guidance to the traders and industrialists. There is need to tighten up these missions.

Some changes have been made recently in the rates of duties on the various kind of cloth and perhaps the duty on controlled cloth has gone up which has adversely affected the masses. This should be rectified.

Presently, there are about 104 sick textile mills under the National Textile Corporation on which we had to suffer huge losses. There is great need to create an intelligence wing in the Ministry with a view to find out as to which of the mills are really sick and which of them have been deliberately made sick by the industrialists. After such scrutiny only the genuinely sick mills should be taken over by the Government. A trained cadre should also be prepared to look after the mills that are taken over.

The price rise is the biggest problem before the country and our performance will be judged by the success we achieve in solving it. The Prime Minister has issued two appeals in this connection. There is no clear indication in the Ministry's report as to how the Government is going to tackle this problem.

First of all a survey should be conducted in respect of essential commodities to find out the actual cost of production and their selling price. There should be a ceiling of profit. At present even 200 per cent profit is being earned on foreign made garments.

The branches of Super Bazar should be opened in colonies inhabited by poor people and in slum areas because they are the most needy persons. There is a big scandal in the import of edible oils. The mischievous elements should be punished.

With these words I support the Demands for Grants presented by the hon'ble Minister.

Sh. Vasant Sathe (Akola) : I hope Sh. Mohan Dharia will be able to do Justice with the important task he has been entrusted with by the new Government.

So far we have been unable to check the rise in prices. Although there was record production of edible oil during 1975-76 yet the price of oil has not come down. It clearly shows that our distribution system is not good. Secondly there is no need based production. We lack morality. So it is useless to issue appeals time and again. This will not help in checking the prices because the traders want to earn profit more and more.

This mixed economy is the biggest unmixed unmitigated evil. Whichever Government is there, there will be no solution to your problems. You can take years. I am not against traders but you have to choose between the two sectors. The persons running the private sector are also Indian citizens but they should be made to discipline themselves. Let every traders be a member of that national sector, whatever you may call it, and not go outside that.

The hon'ble Minister has praised the small sector which produces much more and which has more employment potential. I know that about one crore people are employed in the handloom industry and only 7 lakh persons are offered employment by the mill sector yet it is the mill sector which has amassed wealth of the country. We have failed to formulate a national policy in respect of textiles.

There is need to allot more money to the cotton Corporation. We should pay more attention to the needs of farmers.

Moreover there is need to creat market for goods produced in the rural areas. Fine and super fine garments can be manufactured in villages and they can create foreign market. Bureaucracy is the biggest evil. We should remain vigilant against it only then we will be able to develop our country.

*श्री ए० मुरुगेसन (चिदम्बरम्) : यह बहुत संतोष की बात है कि वर्ष 1976-77 के दौरान हमारा निर्यात 4,981 करोड़ रुपये तक पहुंच गया । यह राशि पिछले 30 वर्षों के दौरान सबसे अधिक है । पर इसके साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस वृद्धि का मुख्य कारण वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का बढ़ जाना है न कि हमारे निर्यात में कोई विशेष वृद्धि होना । हमारी परम्परागत वस्तुओं जैसे चाय, चीनी, काफ़ी, चमड़ा, चमड़े की वस्तुओं, काली मिर्च आदि के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में बढ़े । अतः हमें निर्यात के मामले में उपेक्षात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिये ।

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि चीनी निर्यात के मामले में पर्याप्त राज सहायता दी जाती है । अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में हम चीनी 75 पैसे प्रति किलो बेचते हैं, जब कि देश के भीतर 4.50 रु० प्रति किलो बेची जाती है ताकि बाहर होने वाली हानि देश में पूरी की जा सके । इस लाभ के लिये चीनी मिल मालिक राजनीति की ओर झुकते हैं । दुर्भाग्य यह है कि आम आदमी चीनी मिल मालिकों और सरकार के बीच में फ़ंसा रहता है ।

यह भी चिन्ता का विषय है कि अन्तर्राष्ट्रीय चाय मंडी में हमारा शेयर कम हो रहा है । पता नहीं इसका क्या कारण है ? हम कच्चा तम्बाकू निर्यात करते हैं। समझ में नहीं आता कि अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय पारखियों के स्वाद को ध्यान में रख कर तम्बाकू उगाने की तकनीकी जानकारी

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

Summarised translated Version based on English translation of speach delivered in Tamil.

का विकास क्यों नहीं किया गया । गत वर्ष पूर्वी योरोपीय देशों को किये जाने वाले निर्यात में कमी हुई । तमिलनाडु में अर्ध-चमड़े के निर्यात पर लगी पाबन्दियों के कारण चमड़ा उद्योग को काफ़ी धक्का लगा है ।

किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का अन्दाजा इस बात से लगाया जाता है इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात कितना है और खाद्य पदार्थों का आयात कितना है । अप्रैल-दिसम्बर , 1976 के दौरान हमने 1425 करोड़ रुपये के खाद्यान्न का आयात किया । इससे पता चलता है कि हमारा देश उद्योग और कृषि दोनों के क्षेत्र में अविकसित है ।

राज्य रसायन तथा फ़ार्मेस्यूटिकल्स निगम ने जापान से काफ़ी मात्रा में पोलीथीन ग्रेनयूल्स खरीदा है । इसके परिणामस्वरूप पोलीथीन, की थैलियां, शीटें, तथा ट्यूब बनाने में लगे हजारों छोटे उद्योगों के बन्द होने की नौबत आ गई है । आई० सी० आई० ग्रेन्यूल्स बना रहा है और वह उनकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए अपना उत्पादन बढ़ा सकता था परन्तु इस निगम ने अपने अस्तित्व का औचित्य दिखाते हुए जापान से पोलीथीन ग्रेन्यूल्स आयात करना शुरू कर दिया । हमें ऐसी अनावश्यक वस्तुओं के आयात में विदेशी मुद्रा खराब नहीं करनी चाहिये ।

राज्य वस्त्र निगम इस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है । हाल में वित्त मंत्री ने बताया कि इस निगम को 114 करोड़ रुपये का आवधिक घाटा हुआ है । बन्द पड़ी मिलों को पुनः चालू करने के लिये ताकि स्टेण्डर्ड कपड़े और निर्यात-योग्य कपड़े का अधिक उत्पादन हो सके, सरकार ने इन कपड़ा मिलों को अपने हाथ में ले लिया । लेकिन उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई । सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात भी संतोषजनक नहीं रहा । निर्यात व्यापार में हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिये विदेशों में स्थित हमारे राजदूतावासों को सक्रिय बनाया जाना चाहिये । व्यापार विकास प्राधिकरण को निर्यात-कार्य की देख-रेख का कार्य सौंपा गया था । पर वह तो एक सफ़ेद हाथी ही सिद्ध हुआ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जानी चाहिये क्योंकि निगम अधिकारी अंग्रेजी या हिन्दी न जानने वाले व्यापारियों के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाते हैं ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Chatra) : Sir, While supporting these demands I will like to draw attention towards two or three things. One can not deny the fact that the prices are rising Some people say that its main cause is decrease in production but I do not agree with this view because in that case things would not have been available in the market. At present things are available but you have to pay more.

Lack of proper distribution system is the main cause for increase in prices. Black money is another force which tends to increase prices. In fact this profit does not go to the poor farmer, it is the middle man who earns huge money an account of profits.

There is a wide disparity in the prices of industrial goods and agriculture goods. Prices in general flactuate because there is no uniformity in the fixation of prices of agricultural and industrial goods. The Minister should think about the measures for streamlining the system of distribution and for bringing about parity in the prices of agricultural and industrial goods.

Cooperatives can be used as an instrument to improve distribution system. But today the condition of these cooperatives is miserable. In order to strengthen the rural economy, it is most essential to have strong Panchayats and Cooperatives in the country. One can find that in Maharashtra and Gujarat Cooperatives have done very well. But the Cooperatives in Bihar State are not functioning satisfactory. Their working is most inefficient. The reason is that Cooperation is still a sate subject. Further farmers are not being benefited by Credit Banks, Land Development Banks and marketing organisations. There is large scale bungling in these organisations.

Further there is too much officialdom in Cooperatives. The elected representatives should have their control on these cooperatives and not the officials. No representation has been given in these cooperatives to those people for whose welfare these have been formed. In Bihar Cooperatives have been reduced to just family institutions. Therefore it is necessary to bring the subject of cooperation under the control of the centre.

Secondly there should be more sources of income of these Cooperatives so that they may have a smooth functioning. Unless the Central Government do not frame a Central Cooperative Act and it is not made applicable to all the states uniformally no break through can be achieved in this regard. It is imperative that their financial position should be strong, only then they can contribute a lot for the development of agriculture.

In order to improve rural economy, strengthening of Cooperatives institutions is most essential and Government should take concrete measures in this direction.

Government should institute enquiries into the working of Cooperative Societies in Bihar. They should try to eliminate the influence of big capitalists in the Cooperative societies. Either Government themselves or the C.B.I. should conduct these enquiries into the working of Cooperative societies in Bihar.

Shri Mritunjay Prasad Verma (Siwan) : Until the law in regard to Cooperatives is charged, there will not be any improvement in the working of Cooperative Societies. The audit of Cooperative Societies should be taken out of the jurisdiction of the Registrar of Cooperative societies. The Registrar supervises the functioning of Cooperative societies. The Audit Department also works under the control of Registrar. So the Audit department can not dare to point out any discrepancy or bungling in the working of Co-operative societies. Under the existing law, the Registrar is empowered to dismiss any complaint about irregularity in the working of any Cooperative societies. No action is taken on the report submitted by the Auditor.

[**Shri Sonu Singh Patil in the Chair**
श्री सोनूसिंह पाटिल पीठासीन हुए]

In fact the general body of a society should be made so effective as it can replace the managing Committee. The law should provide that Registrar must pay heed even to individual complaints. Investigations must be made at least in regard to *prima facie* cases. The audit organisation should be completely independent of Registrar.

As regards our trade we should not export those commodities which are needed most for domestic consumption. Then other commodities such as, minerals, or raw materials which will not be replaced should also not be exported. It is wrong to build up our economy on the basis of export of minerals or raw materials. We should stop our export of raw materials and import of finished goods.

State trading is not making much headway because the behaviour of employees in Super Bazar Stores or consumer Cooperative Stores with the customers is not conducive to higher sale. They should be instructed to work in business like manner. Further only efficient persons should be entrusted with the jobs of running the Cooperative Society.

श्री बयालार रवि (चिरयिंकील) : सर्व-प्रथम मैं मंत्री महोदय का ध्यान तेजी से बढ़ती हुई कीमतों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपात स्थिति के प्रथम 6 महीनों के दौरान मूल्यों में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई थी किन्तु 1976 के दूसरे भाग में मूल्यों में 1 प्रतिशत गिरावट आई। खाद्यान्नों, दालों, सब्जियों, दूध, मांस आदि के मूल्य में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सामान्य मूल्य स्तर में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गत तीन महीनों में फलों के मूल्य में 29.4 प्रतिशत, खाद्यान्नों के मूल्यों में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बड़ी गंभीर समस्या है और इसे हल करने के लिए भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। हमें मूल्यों पर नियंत्रण पाने के लिए कोई न कोई उपाय करना चाहिए।

भूतपूर्व सरकार ने मुद्रा सप्लाई कम करके मूल्यों को रोकने का प्रयास किया। किन्तु मूल्यों को बढ़ने से रोकने का यह स्थायी तरीका नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान सरकार भी मुद्रा सप्लाई कम करके इसका हल निकालना चाहती है। मेरी राय है कि इस समस्या का हल अधिक उत्पादन तथा बेहतर वितरण प्रणाली द्वारा किया जा सकता है। यह अच्छी बात है कि हजारों जनता दुकानें खोली जा रही हैं। किन्तु आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर समुचित लोक वितरण प्रणाली द्वारा ही नियंत्रण पाया जा सकता है। कठिनाई से पांच या 6 ही आवश्यक वस्तुएं हैं जिनकी कि ग्रामीण जनता को आवश्यकता पड़ती है। हमें ग्रामीण तथा शहरी जनता की आवश्यकताओं को देखना है और तभी मूल्यों पर नियंत्रण करना है।

चाहे भूतपूर्व सरकार थी अथवा वर्तमान वाणिज्य मंत्रालय अच्छे कार्यकरण के लिए बधाई का पात्र है। विश्व व्यापार में 11 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है किन्तु हमें यह देखना है कि इसमें हमारा कितना भाग है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इस संबंध में हमें कुछ मुख्य निर्णय लेने चाहिएं। भारत तथा ग्रुप 77 के अन्य देशों का शोषण किया गया है। हमें इस शोषण को रोकना है। आपके ही प्रतिवेदन के अनुसार अमरीका के साथ हमारा निर्यात 0.5 प्रतिशत है जबकि अन्य लेटिन अमरीकन देशों का निर्यात 12.4 प्रतिशत है। यह सब राजनीतिक कारणों से है।

निर्यात व्यापार में कुछ सुधार हुआ है किन्तु यह सब केवल आयात में कमी के कारण हुआ है। 1976-77 में आयात में 39 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यद्यपि उर्वरक आदि का देश में अधिक उत्पादन हुआ था तो भी इन वस्तुओं का 1000 करोड़ रुपये तक का आयात किया गया। हमें देखना है कि हम किन-किन वस्तुओं का आयात रोक सकते हैं।

हमने दुलर्भ मुद्रा वाले देशों को अपना निर्यात बढ़ाने के लिए भी सराहनीय प्रयास किया है। हमें आर्थिक समूह वाले देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए। निर्यात के लिए अधिक अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज की जानी चाहिए। खाड़ी देशों के साथ भी हमारा व्यापार पर्याप्त नहीं होता। हम उनके साथ व्यापार संबंध बढ़ा सकते हैं। केरल राज्य पारम्परिक वस्तुओं के निर्यात से लगभग 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाता है। हर्ष की बात है कि हमने 550 करोड़ रुपये मूल्य का इंजीनियरी सामान भी निर्यात किया है। हमें काफी, रबड़, इलायची तथा सामुद्रिक उत्पादों का अधिकाधिक निर्यात करना चाहिए। आपने काफी के निर्यात पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया है। इसमें कमी की जानी चाहिए।

सामुद्रिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष कुछ नहीं किया गया है। हम इनसे 186 करोड़ रुपये कमा रहे हैं। यदि इस ओर ध्यान दिया जाये तो हम 210 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य से अधिक धन कमा सकते हैं। मूंगफली का तेल केरल में खाने के तेल के रूप में उपयोग में किया जाता है। मूंगफली समूचे पश्चिमी घाट में पैदा की जाती है। केरल की अर्थ-व्यवस्था मूंगफली पर निर्भर करती है। इसका निर्यात करने से वहां के लोगों को बहुत घाटा हुआ है। मूंगफली का निर्यात बंद किया जाना चाहिए।

Shri Dharamsinhbhai (Porbandar) : I support the demands for grants in respect of Commerce Ministry. The former Government had claimed the forward trading in groundnut, groundnut oil, cotton, cotton seeds and castor etc. This has not only deprived the Government of its lawful revenue but has also given rise to corruption. I would therefore, suggest that forward trading on the above commodities should be allowed to be resumed.

Presently cooperative societies are charging 15 per cent interest from agriculturists in rural areas while Reserve Bank advances money to rural banks at the rate of 7 per cent per annum. Steps should be taken to bring down rate of interest for agriculturists to 9 per cent and to reduce multiplicity of banking agencies. A separate corporation to deal with edible oil should be established.

The former Government imposed so many rules and regulations on trade and business with the result that quota permit and licence system came into being. I will urge the Government to do away with unnecessary licences and permits so that corruption and harassment on that account could be reduced.

So far as Gujarat state is concerned it has not so far received its full quota of cement. The Minister should see that the state is allotted its full quota of cement.

Shri Tej Pratap Singh (Hamirpur) : I want to draw the attention of the Minister towards Cooperative movement...It is a universally accepted principle that those who are in charge of co-operative institutions should be elected persons. But in U.P. during the last few years laws relating to cooperatives were changed in a manners which ignored the basic principles of cooperation. The elected people could be removed from office. People expect from the Janata Government that they will not interfere in the working of cooperatives.

Corruption is rampant in the cooperative movement. The Congress Government have nominated such people who had no connection with cooperatives. The elected persons should be chairman of cooperative institutions and should be given all respect. The rules etc. in the states should be amended to make such a provision. A model Act should be prepared for all the states in consultation with National cooperative Union of India so that basic tenets of cooperation are protected. The size of cooperative society should also be decided.

A prominent roll has been assigned to the cooperative movement in the five years plans but in actual practice, the position was otherwise The congress Government has not implemented what has been stated in five year plans in regard to the role of cooperative movement in the socio-economic transformation of the country.

News have appeared in the press that Minister has put forward a proposal to have cooperative stores like Super Bazar for weaker sections. The proposed 1000 stores should be opened at places where common people could take advantage.

Policy of sale of sugar at controlled price and in the open market should be changed. In cities well to do people got sugar at controlled price whereas in villages poor people have to purchae sugar at a high price in the open market. This policy of having two prices of sugar should be changed.

A man having experience in cooperative movement should be made chairman of NCDC. It is hoped that under the able guidance of the Minister, this movement will make great headway.

श्री चित बसु (बारसात) : मैं विचाराधीन मांगों का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय देश को समाजवाद की ओर उन्मुख करेंगे। पटसन और कपड़ा हमारी अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं और ये दोनों मंत्री महोदय के सीधे नियंत्रण में हैं।

पटसन उद्योग आज संकटग्रस्त है जिसका कारण कुप्रबन्ध तथा धोखा आदि आदि है । भूतपूर्व मंत्री प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय ने भी इस बात को माना है कि इस उद्योग के संकट मालिकों के दोष के कारण हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उद्योग को संकट से मुक्त करने के लिये क्या करने जा रही है ? एक सबसे बड़ी समस्या कच्ची पटसन की उपलब्धता तथा मूल्य भी हैं। पिछले तीस वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम के ग़रीब किसानों का शोषण किया गया है।

पिछले वर्ष कच्ची पटसन के मूल्य 135 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किये गये जबकि इस वर्ष के लिये कोई मूल्य निश्चित नहीं किये गये। 135 रुपये का मूल्य बहुत कम है जो 200 रुपये से कम किसी भी दशा में नहीं होने चाहियें। मंत्री महोदय को पटसन की उत्पादन लागत का अनुमान लगाना चाहिये। पश्चिम बंगाल के पटसन कारखानों के मालिक 200 रु० अथवा 235 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बाजार से कच्ची पटसन खरीद रहे हैं जबकि किसानों को 135 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दे रहे हैं। भारतीय पटसन निगम प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुआ है। भारतीय पटसन निगम ने कुल पैदावार की 80 लाख बेलों में से केवल 6-7 लाख बेलें खरीदीं हैं । पटसन के तैयारशुदा माल के मूल्य की तुलना में कच्चे पटसन के मूल्य नहीं बढ़े हैं । सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और कच्ची पटसन के लाभकारी मूल्य निश्चित करने चाहिये। इस संबंध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान श्री निर्मल चन्द्र सेन समिति रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं।

निर्यात में वृद्धि हुई है और आय में भी वृद्धि हुई है। लेकिन कच्ची पटसन के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

कपड़ा और पटसन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। सरकार को इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिये। ऐसा किये बिना हमारी अर्थव्यवस्था मज़बूत नही हो सकती ।

Shri Motibhai R. Chaudhary (Banaskantha) : I support the demands of grants presented by the Minister. It is well known fact that Dairy industry has great potential for providing employment to people in rural areas. For proper development of this industry, it is necessary to ensure proper prices of cattle feed. The Government should stop export of oilcake in order to help this industry.

Essential commodities like onions, potatoes, and bananas should not be exported. Common people suffer is prices of these essential commodities rise. Import of cotton should be stopped. Cotton growers should be helped in a big way to increase cotton production in the country.

More and more sugar cooperative factories should be started. Instead of nationalising sugar industry it will be better to have more cooperative sugar factories. That will increase employment in the rural sector.

Use of ambar charkhas should be encouraged by the Government. Instead of spending money on spinning millls the Government should give more assistance for ambar charkhas.

Presently, Government is spending valuable foreign exchange worth crores of rupees for importing fertilizers. Instead of doing that we should set up more and more fertilizer factories in the country.

Handloom industry should be developed on priority basis so that we are able to tackle the problem of unemployment. Production of sarees and dhoties should be reserved for handloom sector. Cooperative Societies at the national level should be given encouragement for growth. Audit of national societies should be conducted in time.

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : आयात नीति को प्रोत्साहन देने से हमारे छोटे-छोटे उद्योगों को क्षति पहुंचेगी। 111 वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन दिया गया है। आयात संबंधी यह उदार दृष्टिकोण चिन्ताजनक है।

मेरे विचार में जिन लोगों को आयात लाइसेंस दिये जायेंगे वे लोग मंत्री महोदय से विश्वासघात करेंगे जैसे कि खाने के तेल के आयात के मामले में हुआ है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण सोमवार को जारी रखें।

इसके बाद लोक सभा सोमवार 27 जून, 1977/6 आषाढ़, 1899 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, the 27th June, 1977/ Asadha 6, 1899 (Saka).

MGIPRRND—6 LSS/77—II N.S.—23-9-77—200.